

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

30.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9.20 बजे

सेवा पर्व—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष शृंखला — 'सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के माध्यम से भारत के लिए एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत के स्कूलों को ऐसे स्थानों में बदलने का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है जहां शिक्षा अब केवल पाठ्यपुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित नहीं रह गई। इस नीति ने भारत में एक अधिक समावेशी, शिक्षार्थी—केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसी पहलों से 8 लाख 90 हजार स्कूलों के 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा अब एक विषय है, जिसके एक हजार से ज्यादा आई.एस.एल. वीडियो और टॉकिंग बुक्स विकसित की गई हैं। बाल वाटिका, जादुई पिटारा और प्रशस्त ऐप सहित अन्य पहलों ने बहुभाषी, समावेशी और समग्र शिक्षा को और बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर रही है जहां प्रत्येक शिक्षार्थी को फलने—फूलने का अवसर मिलता

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने निजी विदेश दौरे से लौटने के बाद बीती शाम दिल्ली से शिमला पहुंचे। मौसम खराब होने के चलते अनाडेल हैलीपैड में उनका हैलीकॉप्टर नहीं उतर पाया जिसके चलते जुब्बडहट्टी हवाई अड्डे पर उतारा गया जहां उपायुक्त अनुपम कश्यप ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपायुक्त ने मॉनसून के दौरान जिले में चल रहे राहत व विकास कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को संक्षिप्त जानकारी दी।

नवरात्र

शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा—अर्चना की जा रही है। माता सौभाग्य, धन—संपदा, सौंदर्य और स्त्री जनित गुणों की अधिष्ठात्री हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में आज सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है।

नाबार्ड

राज्य सरकार सड़कों, पुलों और ग्रामीण पेयजल—सीवेज परियोजनाओं के निर्माण व सुदृढीकरण के अलावा बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर 4 सौ 19 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विकास कार्यों के लिए आर.आई. डी.एफ. के तहत नाबार्ड ने इस राशि को बतौर वित्तीय ऋण मंजूरी दे दी है। सरकारी विभागों को अपने—अपने विभागों में स्वीकृत परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन कर 30 दिन के भीतर नाबार्ड को भेजना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायकों की प्राथमिकता के अनुसार योजना विभाग ने नाबार्ड से बजट का प्रावधान करवाया है।

कूड़ा शुल्क

पर्यटन नगरी राजधानी शिमला में बाहर से आने वाले सभी बड़े यात्री वाहनों को कूड़ा शुल्क चुकाना होगा। एचआरटीसी और निजी बसों के अलावा बाहर से आने वाली बसों से भी ये शुल्क लिया जाएगा। शिमला नगर निगम ने कूड़ा शुल्क की दरें तय करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है—सड़कों पुलों और पेयजल योजनाओं के लिए नाबार्ड से 4 सौ 19 करोड़ रूपए मंजूर। दैनिक सवैरा टाईम्स लिखता है—नाबार्ड से हिमाचल के 4 सौ 19 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर। दिव्य हिमाचल ने इसी खबर को सुर्खी दी है— सड़कों, पुलों, पानी पर खर्च होंगे 4 सौ 19 करोड़।

पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है—भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं, चाहे मंत्री विधायक या अफसर हो, क्रपशन करने पर होगी सख्त कार्रवाई।

दिव्य हिमाचल ने सांसद कंगना रणोत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है—कंगना रणोत को झटका, भटिंडा कोर्ट में पेश होना ही होगा।

हिमाचल दस्तक लिखता है—सरकार के नए मुख्य सचिव की ताजपोशी पर आज होगा फैसला। इसी अखबार की एक अन्य खबर है— शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू 3 को फिर जा सकते हैं दिल्ली।
